गतांक की चीर-फ़ाड़

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

भारत में न्याय पाना कितना कठिन व महंगा है!

मज़दूर मोर्चा के 8-14 जुलाई 2018 के अंक में राष्ट्रीय क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। पुलिस, राजनीतिक नेता विशेषकर सत्ताधारी नेता व दबंगों का गठजोड़ सदैव रहता आया है। यदि सामने कोई धनवान व राजनीतिक पहुंच वाला दबंग हो तो उसको न्याय मिलने की आशा हो जाती है। जिसका 'पुलिस अफ़सर का बेटा डकैत, मंत्री पैरोकार: ऐसे हुआ था न्याय का बंटाधार' में उचित विवेचन किया गया है। इस प्रकरण से यह कहावत ठीक चरितार्थ होती है कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाय तो उस देश व समाज का क्या हश्र होगा?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़े कॉरपोरेट घरानों जैसे अडानी, टाटा, अम्बानी, एस्सार आदि को लाभ पहुंचाने के लिये कानून, कायदे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कोई परवाह नहीं करते तथा उन्हें आम आदमी के हितों से सरोकार नहीं है। अडानी, टाटा व एस्सार तीनों कम्पनियों ने बिजली दरें बढ़ाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इन कम्पनियों को अपने उपभोक्ताओं पर बोझ डालने से रोक दिया। आदेश की अवहेलना करते हुये मोदीजी ने अपनी चहेती कम्पनियों को लाभ देने के लिये सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज की अध्यक्षता में पैनल बना दिया जिसे परचेज एग्रीमेंट्स की समीक्षा करने के बाद दर में बढोत्तरी करने या इन प्रोजेक्ट्स को एक्विजिशन करने जैसे सुझाव देने का अधिकार दे दिया, जिसका 'मोदी की चली तो बिजली के बिल डेढ से दो गुना हो जायेंगे' में पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है।

सत्ताधारी तथा विपक्षी पार्टियां सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों को टोल बैरियर पर गुजरने वाले वाहन से टोल वसूल करने का लाइसेंस प्रदान करते हैं, जबकि वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय वाहन मालिक से रजिस्ट्रेशन फ़ीस, रोड टैक्स आदि वसूल लिया जाता है। पिछले लोक सभा चुनाव (2014) के समय नितिन गडकरी ने चुनावी रैली में वादा किया था कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो देश में टोल नाके समाप्त कर दिये जायेंगे। स्थानीय केन्द्रीय मंत्री कृष्ण पाल ने भी टोल को लेकर बदरपुर बैरियर पर बवाल काटा था। परंतु चुनाव जीतने के बाद टोल हटाने का वादा एक जुमला बन कर रह गया। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी ने तो फ़रीदाबाद-गुड़गांव सड़क पर बने बैरियर पर टोल टैक्स में तीसरी बार वृद्धि कर दी है, जिसका 'फ़रीदाबाद-गुड़गांव टोल बैरियर पर मनमानी दरें-सरकारी संरक्षण में बढ़े लूट के भाव, विपक्षी भी बहा रहे घड़ीयाली आंसू' में पूरा खुलासा किया गया है।

'मोदीजी की डिग्री वाकई कमाल की है' में मोदीजी द्वारा अज्ञात विषय एंटायर पोलिटिकल साईंस में एम.ए.प्रथम श्रेणी की डिग्री लेना, वह डिग्री भारत में कंप्यूटर आने से 10 वर्ष पहले कम्पयूटर से प्रिंट होने, आपात काल के दौरान भूमिगत रहते हुये दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षा देना आदि मुद्दों के संदर्भ में मोदीजी के शैक्षनिक योग्यता व एम.ए. की डिग्री पर उपयुक्त सवालिया निशान लगाया गया है। आश्चर्य है कि इस विवाद पर मोदी जी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्मरण रहे कि केन्द्रीय कपड़ा मंत्री व पूर्व मानव संशाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी की भी शैक्षणिक योग्यता विवादित रही है। गौरतलब है कि अम्बानी बन्धुओं द्वारा स्थापित होने वाले जियो इंस्टिट्यूट को खुलने से पहले ही उत्कृष्ट संस्थान के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। संशय है कि मोदी सरकार की विवादित शैक्षणिक परिस्थितियों के मद्देनज़र देश में शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार होगा?

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के अंतर्गत रायकाशीपुर गांव में दलित ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर कट्टर हिन्दुत्ववादियों ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। मौजूद लोगों, जिनमें महिलायें व बच्चे भी शामिल थे, को दौड़ा-दौड़ा कर निर्ममतापूर्वक पीटने का 'भगवा तालिबानियों ने धार्मांतरण के नाम पर दलितों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा' में बेबाक विवेचन किया गया है। हर घटना और हमले के बाद हिन्दुत्ववादी भगवा गैंग पीड़ितों पर धर्मांतरण, गौ हत्या, गौ मांस आदि का आरोप लगाता रहा है और भाजपा सरकारों द्वारा इन कट्टर हिन्दुत्ववादियों के विरुद्ध कोई प्रतिरोधात्मक कार्यवाही नहीं की जाती। महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है कि क्या दलित व अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, ईसाई आदि को इन कट्टर हिन्दुत्ववादियों के रहमों करम पर रहना होगा।

आरएसएस व मोदी दोनों देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के नाम से ही खौफ़ में रहते हैं तथा नेहरू को अपने लिये चुनौती मानते हैं। इसलिये वे नेहरू को खंडित करने व झूठ फ़ैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और उन्होंने अपने चारों ओर झूठ से गढा हुआ नेहरू का भूत खड़ा कर लिया है जिसका 'भगत सिंह और नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है, वो गलत नहीं बल्कि झूठ है' सटीक विश्लेषण किया गया है। वैसे तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि मोदी को एतिहासिक तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है और वे झूठ का इतिहास रचने में माहिर हैं।

संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य नेता मध्यकालीन निरंकुश शासकों की तरह दरबार लगाते हैं चाहे सामंती शासन का जमाना चला गया है जिसकी 'राज दरबार में अपमानित लोकतंत्र' में समीक्षा की गयी है। विडम्बना है कि लोकतंत्र के नाम से चुनाव जीतकर सत्ता में आने के बाद वे लोकतंत्र का मजाक बनाने में लग जाते हैं।

2014 के लोकसभा चुनाव के समय नरेन्द्र मोदी द्वारा अच्छे दिन आने के आश्वासन पर 'अच्छे दिन', बेरोज़गारों को नौकरियां न दिलाये जाने के बाद पकौड़े बेचने का कहने पर एम्पलॉयमेंट डाटा-ये लो पकौड़ा तथा बीते चार वर्षों में 165 दिन विदेश में रहने पर 'सर!! ये डॉयलॉग यहां नहीं....क्योंकि आज हम भारत में हैं- मैं हमेशा से ही इस धरती पर आने की चाह रखता था.....' कार्टूनों द्वारा मोदी की नीतियों व भाषण पर उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।

भाजपा को सीएम मनोहर लाल की ईमानदारी पर भरोसा है और अधिकारी दिनों दिन मालामाल होते जाते हैं

करनाल (उप्पल) यदि आप ऊपर लिखे शीषर्क को समझ नहीं पाए तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि सीएम सिटी करनाल की जनता का दर्द अब सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही दिखाई व सुनाई देता है। सरकार अभी भी फीलगुड में है और आम जनता गुस्से में।

स्मार्ट सिटी करनाल को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खा रहा है लेकिन भाजपा को भरोसा है कि सीएम मनोहर लाल की ईमानदारी का मेडल उनकी नैया पार लगा ही देगा। हालांकि अंदर खाते सभी सच्चाई को जानते है लेकिन पानी में रहकर दुश्मनी कौन लेता है?

स्मार्ट सड़क बनाते बनाते सीवरेज के ढक्कन भी दबा गए,डाक्टरों ने खोला मोर्चा तो जागे अधिकारी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज के सामने बनाई जा रही सड़क के निर्माण कार्य पर मानो करनाल प्रशासन ने सीएम मनोहर लाल का मजाक उड़वाने में कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऐसा कारनामा कर दिया कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तालमेल की कमी के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग ने पब्लिक हेल्थ के बनाये सीवरेज को सड़क के नीचे ही दबा दिया।

शहर के दो बड़े और जाने माने डाक्टर जीडी शर्मा और सीके ठाकुर ने खुलेआम आरोप लगाए कि सीएम सिटी में लापरवाही का ये आलम उनके हस्पताल और घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि बिना ढक्कन खोले सीवरेज की सफाई नहीं हो सकती और सीवरेज बैक मारकर चोक होने लग गए।उन्होंने बताया कि सीवरेज का गंदा पानी उनके आपरेशन थियेटर तक आ गया है लेकिन कई शिकायतों के बाद भी जिला प्रशासन उनकी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं है।

20 लाख की रिश्वत मांगने के आरोपियों पर सरकार मेहरबान,बिना जांच ही 4 आरोपी बहाल। जनवरी 2018 की शुरुआत में करनाल में राईस मिलर्स ने वेरिफिकेशन के नाम पर मार्केटिंग बोर्ड के अफसरों पर 20 लाख रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए एक सीडी जारी की थी। मामला पहले मीडिया में आया और फिर मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में। मामले पर शुरुआती कार्यवाही तो ऐसे शुरू हुई जैसे दिनों दिन रिश्वतखोर अधिकारियों को जेल में डाला जाएगा लेकिन गम्भीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद 4 अधिकारी खुले आम घूमते रहे।

हालांकि, पुलिस ने समय समय पर दावा किया कि वो लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन इस बात के भी पुख्ता प्रमाण हैं कि आरोपी अधिकारी खुलेआम घूम रहे थे लेकिन पैसे और सिफारिशों के आगे सभी नतमस्तक नजर आए। अब मामले में यू टर्न ये है कि आरोपी 6 अधिकारियों में से चार आरोपियों को जांच के दौरान ही बहाल कर दिया गया है।

एसआईटी भी उन्हें क्लीन चिट देने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि अफसर जो कल तक भगौड़े थे एकाएक बहाल कैसे हो गए? क्या इन्हें सीएम मनोहर लाल ने अपना आशीर्वाद दे दिया या पैसों की ठंडी हवा लेने से सरकार के बड़े अफसर खुद को रोक नहीं पाए या मामला कुछ और है?

लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आखिर सीएम सिटी में भ्रष्टाचार का ये कैसा जीरो टॉलरेंस है जिसे आम जनता पचा नहीं पा रही और सरकार के स्तर पर इसे कोई एहमियत नहीं दी जा रही?

इसके बाद कृषि विपणन बोर्ड की बनाई सड़कों की बात भी कर लें क्योंकि यहां तो जो कारगुजारियां अधिकारियों ने कर दी उससे तो इस बात पर ही सन्देह है कि क्या हरियाणा सरकार अपनी आंख और कान का इस्तेमाल करती भी है या फीलगुड का दौर उसे ये बता रहा है कि जनता के बीच इन मुद्दों की कोई एहमियत ही नहीं है?आपको बता दें कि करनाल और यमुनानगर में कृषि विपणन बोर्ड की बनाई सड़को में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन कार्यवाही के नाम पर फिलहाल नतीजा सिफर है। हालांकि जो सूचना हमें सीएम कार्यालय से मिली है उसके अनुसार सीएम ने खुद इस मामले पर कार्यवाही के लिए कहा है लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या ये कार्यवाही भी वैसी ही होगी जैसी अभी तक होती आई है?

करनाल के दरड़ संगोहा, गोबिंदगढ़, रैयतखाना,गोंदर, में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो सड़कें करोड़ो का बजट दिखाकर बनाई गई हैं उनमें न तो बर्म को बनाया गया न ही सड़क की गुणवत्ता बढ़िया निकली। आलम कुछ यूं हुआ कि सड़कें बनते- बनते ही टूट गई लेकिन अधिकारियों ने पत्रकारों को चुनौती दे डाली की जाओ सैंपल फेल करवाके दिखाओ? मार्केटिंग बोर्ड का जेई सुशील काम्बोज यही नहीं रुका उसने तो यहां तक कह दिया कि चाहे सीएम को शिकायत करो या किसी अफसर को ये सड़के बिल्कुल ठीक बनी हैं हालांकि कुछ सड़को पर तो यही सन्देह है कि वो जमीन पर बनी भी है या कागजो में ही उन्हें बना दिया गया है?

ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि ईमानदार मुख्यमंत्री के दम पर दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी नहीं बल्कि आम जनता ही दोबारा सत्ता में ला सकती है जिसे कभी पर्दे की आड़ में जनता दरबार मे बुलाया जाता है तो कभी शिकायतों के बाद समझौता करने की नसीहत दी जाती है।

सी एम स्मार्ट सिटी की पोल खुली

गत दिवस बारिश हुई और सी एम स्मार्ट सिटी की पोल खुली। निकम्मे अधिकारियों के कारण हर बारिश में करनाल का रेलवे रोड, बस स्टैण्ड रोड पर गंगा जमना बहने लगती है।

कांग्रेस राज से लेकर खट्टर सरकार के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जल भराव की निकासी का कोई प्रबन्ध नही किया गया। रेलवे रोड के किताबों के दुकानदार सड़क के दोनों और रस्सियां बांध कर आने आने वाले वाहन पर रोक लगा देते हैं ताकि आने जाने वाले वाहनों के वेग से पानी दुकानों के अन्दर न घुस सके । परन्तु इस रोक के बावतूद भी पानी दुकानों के अन्दर चला जाता है जबकि बस स्टैण्ड रोड पर बसों, कारों आदि के आने जाने से पानी दुकानों के आखिरी छोर तक चला जाता है। सड़क के दोनो ओर टाईले लगाई गई परन्तु उनकी लैवलिंग नही की गई। बरसात का पानी मेन होल के जरिये नालों में न जाकर सड़क और टाईलों पर भरा रहता है।

इसके इलावा हुड्डा के कई क्रीम ऐरिया में जल भराव देखा गया है, गर्वनमैन्ट स्कूल एस डी माडल स्कूल, अनाथ आश्रम रोड पानी जमा ही रहता है।

घन्टा घर चौक पर मेन होल पर पानी की निकासी इतनी कम है कि बरसात का पानी जमा ही रहता है, उसे निकलने में घन्टों लग जाते है ।

भगवा तालिबानियों ने धर्मांतरण के नाम पर दलितों को दौड़ा—दौड़ा कर मारा

सुशील मानव की विशेष रिपोर्ट

जनज्वार। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना के अंतर्गत रायकाशीपुर गांव करीब दो दर्जन भगवा तालिबानियों ने असलहे समेत हमला कर दिया, उत्तर प्रदेश में किसे कौन सा धर्म अपनाना है, किसकी पूजा करनी है ये तय कर रहे हैं भगवा तालिबानी।

उत्तर प्रदेश में भगवा तालिबान का आतंक अपने चरम पर है। संविधान और कानून का इनके राज में कोई मतलब ही नहीं है। हो भी कैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया लोकतंत्र के सारे स्तम्भों को तो भगवा तालिबान ने बंधक बना रखा है।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना के अंतर्गत रायकाशीपुर गांव में 1 जुलाई को दलित ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर गाड़ियों में सवार होकर आए करीब दो दर्जन भगवा तालिबानियों ने असलहे समेत हमला कर दिया और वहां मौजूद लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर निर्ममता पूर्वक मारा-पीटा।

भगवा गैंग की बर्बरता का आलम ये कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक को भी नहीं बख्शा। वहां रखी धार्मिक मूर्तियों और दस मोटर साइकिलों को तोड़फोड़ दिया गया। साथ ही भय और आतंक पैदा करने के लिए फायरिंग भी की गई, जिससे चारो ओर दहशत फैल गयी।

भगवा तालिबानियों द्वारा किए गए इस सुनियोजित हमले में घनश्याम, डब्बू गौतम निवासी रायकाशीपुर,अजय गौतम निवासी मोहम्मदपुर सुहाग, राजेश कनवा, सुरेश कुमार,महरानीदीन निवासी सिटकहिया, जियालाल निवासी विजयीमऊ, द्रोपदी निवासी जबलपुर धर्मेंद्र कुमार व प्रियांशी निवासी कर्माइन, प्रकाश निवासी लोकापुर, अर्जुन पटेल निवासी खैरा, पुत्तीलाल, राम सजीवन निवासी सागर रायकाशीपुर, धीरज निवासी रुमतपुर, मुन्नालाल भदशिव समेत बीस लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

पीड़ितों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुँची। पुलिस प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज गुस्साये पीड़ित लोग संग्रामपुर थाने पहुँच गये। तब जाकर योगी आदित्यनाथ की निर्लज्ज पुलिस ने रामकुमार गौतम की तहरीर पर रायकाशीपुर निवासी राजेंद्र सिंह, उसके बेटे रोहित सिंह, शिवम पांडेय निवासी मुरैनी, विवेक तिवारी निवासी सरैया नौवड़िया के अलावा 20 अज्ञात लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया। हमले में घायल रामकुमार गौतम इस घटना को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो चुनाव में आरोपी के खिलाफ थे, इसीलिये उन्हें जानबूझकर गलत बहाने से निशाना बनाया जा रहा है।

बता दें कि रायकाशीपुर निवासी राम कुमार गौतम की ओर से अपने घर पर ही अक्सर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। जहाँ यीशू दरबार भी लगता रहा है। सोमवार को भी ऐसी ही एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। यही कोई दोपहर का समय था और वहां काफी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे, यीशू भजन और कीर्तन किया जा रहा था। राम कुमार गौतम के घर पर सभी लोग यीशू कीर्तन पर और प्रार्थना में लीन थे। इसी दौरान अचानक चार गाड़ियों में भरकर करीब दो दर्जन असलहाधारी अचानक वहां आ धमके और वहां मौजूद लोगों को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।

दूसरी ओर जैसा कि हर घटना और हमला के बाद हिंदुत्ववादी भगवा गैंग धर्मांतरण का आरोप लगाता रहा है यहाँ भी कह रहा है कि प्रार्थना (चंगाई सभा) के बहाने लोगो का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। दरअसल रायकाशीपुर में रामकुमार गौतम के घर पर यह चंगाई सभा कोई नई बात नहीं थी। करीब दो साल से उनके घर यीशू दरबार लगना शुरू हुआ और फिर इसमें शामिल होने वाले लोगो की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती चली गयी।

अगर धर्मांतरण हो भी रहा हो तो क्या तो उससे निपटने के लिए देश में पुलिस प्रशासन और कानून नहीं है। पुलिस में सूचना देने के बजाय भगवा तालिबानियों ने दलित समुदाय के लोगों पर हमला क्यों किया? भगवा आतंकियों के पास इतनी अधिक मात्रा में गैरलाइसेंसी हथियार असलहे कहाँ से आये? क्या इसे किसी कट्टर हिंदू संगठन द्वारा इन्हें मुहैया करवाया गया था?

दूसरा बड़ा सवाल ये कि सूचना के बावजूद पुलिस घटनास्थल तक क्यों नहीं पहुँची, जबकि पीड़ित खुद थाने पहुंच गये। क्या पुलिस की जानकारी में उनकी मिलीभगत से भगवा अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया?

क्या अब संविधान के अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का देश में कोई अर्थ नहीं रह गया है? क्या अब देश का कानून भगवा गैंग की लाठी से चलेगा? क्या अब लोगो को वही सब करना होगा जो ये भगवा तालिबानी चाहेंगे?